

दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला, बारिश और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की राजधानी दिल्ली में कड़की धूप और बढ़ती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले चार दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में यह बदलाव 28 मार्च से सक्रिय हो रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिलेगा, जिसके चलते दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बृहस्पतिवार देर रात से ही आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच गरज-चमक के साथ हल्की फुहारें गिरने के आसार हैं। हालांकि 28 मार्च को मौसम थोड़ा शांत रह सकता है, लेकिन 29 मार्च को एक बार फिर बादलों के बरसने की प्रवृत्ति संभावना है। इससे अधिक प्रभाव 30 मार्च को देखने को मिल सकता है, जब दिल्ली में 30 से 40 कीलॉमीटर प्रति घंटे की चपत से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश के साथ मौसम खुशनुमा हो जाएगा। इस बदलाव के बाद तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इससे पहले, बृहस्पतिवार को दिल्लीवासी तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान रहें। दिन का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का अधिकतम स्तर 77 प्रतिशत और न्यूनतम 25 प्रतिशत रहा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाली यह बूंदबांदी मार्च के अंत में बढ़ते चरण पर गंभीर लगाएगी और धूल भरी हवाओं से भी राहत दिलाएगी।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भारत-मिडिल ईस्ट के बीच 22 नई फ्लाइट बढ़ाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुक्रवार के लिए अद्यतन अंतरराष्ट्रीय उड़ान कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें भारत और पश्चिम एशिया के प्रमुख गंतव्यों के बीच संचालित होने वाली 22 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानों की पुष्टि की है। एयरलाइनों ने बताया कि संशोधित योजना क्षेत्र में वर्तमान यात्रा पैटर्न और परिचालन आवश्यकताओं को दर्शाती है। मीडिया रिपोर्ट में बयान के मुताबिक एयर इंडिया जेड से आने-जाने वाली चार निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें दिल्ली और मुंबई से दो-दो उड़ानें शामिल हैं। मुंबई-रियाद मार्ग पर दो और निर्धारित उड़ानें संचालित होंगी। बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस मरकट और रियाद से आने-जाने वाली चार-चार उड़ानों के साथ इन मार्गों को और मजबूत करेगी। मरकट की उड़ानें दिल्ली और मुंबई से संचालित होंगी, जबकि रियाद की उड़ानें बंगलुरु और कोल्लिकोट से शुरू होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एयरलाइनें हवाईअड्डों पर उपलब्ध स्लॉट और मौजूदा जमीनीपरिस्थितियों के आधार पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय से आने-जाने वाली आठ अनियमित उड़ानें भी संचालित करेगी। इन अनियमित उड़ानों का उद्देश्य यात्रियों की भारी मांग को प्रबंधित करना और उनके लिए अधिक क्षमता सुनिश्चित करना है। प्रेस नोट में उस दिन की निर्धारित, अनियमित और अस्थायी रूप से निरालिप्त सेवाओं की पूरी सूची दी गई है। जेड, रियाद और मरकट जैसे मार्गों पर नियमित उड़ानें जारी रहेंगी, जबकि दुबई और अबु धाबी समेत यूएई के कुछ एयरपोर्ट पर केवल अनियमित उड़ानें ही चलेंगी।

पेड पीरियड लीव: कर्नाटक सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची 15 कामकाजी महिलाएं

जयपुर (एजेंसी)। बंगलुरु, (इंएमएस)। कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं के लिए पेड पीरियड लीव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर 2025 को सभी सरकारी और निजी सेक्टर की महिलाओं को हर महीने एक दिन की पेड पीरियड लीव देने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत महिलाओं को उस दिन की सेलरी भी मिलेगी। हालांकि, कर्नाटक सरकार के आदेश के खिलाफ अब बंगलुरु की 15 निजी कंपनियों में मैनेजर पद पर कार्यरत महिलाओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इन महिलाओं का तर्क है कि पुरुष और महिला के बीच अलग नियम बनाना कार्यस्थल पर समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस तरह की अन्यायपूर्ण छुट्टी महिलाओं को कमजोर दिखाने वाली सोच को बढ़ावा देती है और नियोजकों को पुरुषों से कम सक्षम समझ सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने रपट के आरोपी को नहीं दी जमानत, भरोसा तोड़ना भी माना अपराध

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इंकार किया है। जस्टिस गिरीश कपूरालिया की बेंच ने आदेश में कहा कि यह मामला केवल बलात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्ते में भरोसे को तोड़ना भी अपराध है। पीड़िता ने आरोपी को अपना भाई मानकर राखी बांधी थी और पीड़िता उस पर भरोसा करती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि एक आईआर में पीड़िता ने घटना विस्तार से बताने का दावा किया कि उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पीड़ित को काबू कर कपड़े से मुंह बंद कर दिया। जस्टिस कपूरालिया ने कहा, फ्रड सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है। पीड़िता ने आरोपी को अपना भाई माना और उस पर भरोसा किया। इन परिस्थितियों को देखकर जमानत देना उचित नहीं है। मामले को 2021 का है, जब 13 साल की नाबालिग ने आरोप लगाया कि आरोपी ने वहाने से होटल ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसी साल रपट का केस दर्ज होने के बाद आरोपी हिरासत में था। मार्च 2026 में उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी के वकील विवेक त्रिपाठी ने जमानत का आधार पर बताया कि आरोपी बीते साढ़े चार साल से हिरासत में है। वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सभरवाल ने अपराध की गंभीरता को देखकर जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में पीड़िता की गवाही पूरी तरह से अभियोजन के पक्ष में है और अब केवल दो औपचारिक गवाहों की जांच बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया कि नाबालिग के प्रति भरोसे का उल्लंघन भी गंभीर अपराध माना जाएगा। अदालत ने कहा कि जमानत देने से न्याय के अधिकार और पीड़िता के विश्वास की रक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

सीएम नीतीश से मिला बेटा निशांत तो कौन सी बड़ी खबर हो गई? कहीं कमाने गए थे क्या?

-कांग्रेस नेता बोले- नीतीश कुमार निपट गए और अब उनके बेटे को निपटाना चाहती बीजेपी

पटना (एजेंसी)। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बिहार कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने शुक्रवार को कहा कि नीतीश कुमार निपट गए और अब उनके बेटे को बीजेपी निपटाना चाहती है। राठौड़ ने अखबारों का हवाला देते हुए कहा कि एक विचित्र खबर छपी है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का 50 साल बरेजंगर पूर जो उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं की रोटी पर पलते हैं, लेकिन कल अपने पिता से मिले। कहा से आकर मिले? कहीं कमाने गए थे कि

चिड़ियाखाना से आकर मिले? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राठौड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बड़ी साजिश है। पहले तो नीतीश कुमार को निपटा दिया या फिर नीतीश कुमार निपट गए, अब उनके बेटे को जगह मिलने से पहले निपटाना चाहती है। नीतीश कुमार का बेटा निशांत जो 50 साल का बरेजंगर है, वह 20 साल से नीतीश कुमार के घर में रहा है। वह उनसे मिला तो कौन सी बड़ी खबर हो गई? बंद कमरे में बात हुई तो क्या नीतीश कुमार के घर पर कोई दूसरा भी सोता है क्या? जनता सोती है क्या?

राजेश राठौड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की साजिश है कि नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके बेटे को भी निपटा दें। उनके बेटे का अखबार में बयान भी छपता है कि 2005 के पहले क्या था? राठौड़ ने कहा कि 2005 के बाद निशांत पिताजी ने बिहार को बरेजंगर बना दिया। सारे चीनी मिल बंद हो गए। आपके पिता को पांच साल के लिए मौका मिलता है तो उसमें भी वो तीन बार सरकार बना लेते हैं। पूरे बिहार को भड़का बना दियाज्दालों, माफिया और कमिश्नरों की सरकार बनकर रख दी है।



रामनवमी जुलूस पर पथराव, मची अफरा-तफरी, कई घायल, एक दर्जन लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर शहर में रामनवमी का जुलूस निकाल रहा था। गुरुवार शाम जुलूस सख्यद बाबा चौक से गुजरा, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोग नाच-गा रहे थे, तभी मस्जिद के पीछे से अज्ञात लोगों ने पथराव फेंकने शुरू कर दिए। इस पथराव में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पथराव होते ही जुलूस में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीड़ को वहां से हटाया। लोगों को समझा-बुझाकर शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मस्जिद के मोलाना समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस एयर शो की खास बात यह है कि इसमें चंडीगढ़ के दो पायलट भी हिस्सा ले रहे हैं। विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह सूर्यकिरण टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि विंग कमांडर दिवाकर शर्मा भी टीम का हिस्सा हैं। तेजेश्वर सिंह आर्मी पिल्फिक स्कूल, चंडी गढ़ के 2005 बैच के छात्र रह चुके हैं। उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संघू भी टीम में शामिल हैं।

चंडीगढ़ में दो दिवसीय एयर शो का आगाज, सूर्यकिरण टीम ने दिखाए रोमांचक करतब



-सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सुखना लेक आम लोगों के लिए बंद

चंडीगढ़ (एजेंसी)। सुखना लेक पर शुक्रवार से दो दिवसीय एयर शो का भव्य आगाज हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में शानदार करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, हालांकि प्रवेश केवल प्री-बुकिंग के आधार पर ही दिया गया।

एयर शो के दौरान हर दिन लगभग 10 हजार दर्शकों के पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुखना लेक को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आयोजन स्थल पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद भी मौजूद रहे। प्रशासन ने दर्शकों के लिए खुले ने बेंचों की विशेष व्यवस्था की है ताकि

बंगाल में बदली भाजपा की रणनीति... ममता सरकार के खिलाफ आज शाह जारी कर सकते हैं चार्जशीट

बड़ी रैलिया के साथ ही डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाएगी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बार पार्टी डॉट-अप (नीचे से ऊपर की ओर) और क्षेत्र-विशिष्ट अभियान पर ध्यान केंद्रित करने में जुटी है। भाजपा का मुख्य लक्ष्य गुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सबसे मजबूत गढ़ कोलकाता और उसके आसपास के जिलों की 100 से अधिक सीटों पर जीत पाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 मार्च को टीएमसी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करने वाले हैं। इसमें सत्ताधारी ममता सरकार के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार का कथन चित्रित दिखाया गया है। इसके साथ ही पार्टी एक श्वेत पत्र भी जारी करेगी, जिसमें टीएमसी सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। बात दें कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोग्य शहरवासियों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2021 के विपरीत इस बार भाजपा डोर-टू-



डोर संपर्क अभियान चलाएगी। लोकल समस्याओं को मुद्दा बना रही है। पिछले चुनाव में भाजपा को केंद्रीय नेताओं को रैलियों पर भरोसा था। भाजपा की नई योजना के मुताबिक, कोलकाता में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक विफलता और हालिया आरजी कर (आरजी कर) जैसे संवेदनशील मुद्दों को उजागर करना

है। वहीं, उत्तर 24 परगना (पानीहाटी) में समस्याओं को मुद्दा बना रही है। पिछले चुनाव में भाजपा को केंद्रीय नेताओं को रैलियों पर भरोसा था। भाजपा की नई योजना के मुताबिक, कोलकाता में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक विफलता और हालिया आरजी कर (आरजी कर) जैसे संवेदनशील मुद्दों को उजागर करना

भाजपा ने कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना के जिलों में 100 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कोलकाता की 29 सीटें वर्षों से टीएमसी का मजबूत किला रही हैं, जहां ममता के डिगगज मंत्री और विधायक चुनाव लड़ते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भाजपा ने इस बार जमीनी नेताओं को अरजीह दी है। भाजपा ने माणिकगला सीट से टीएमसी छोड़कर आए तापस राय, भवानीपुर से शुभेंद्र अधिकारी को उतारा है।

उत्तर बंगाल में 2021 में भाजपा यहां मजबूत स्थिति में थी। 34 सीटें मिली थीं। इस बार लक्ष्य 54 में से 45 सीटें जीतने का है। पार्टी यहां न्यू-थॉट बंगाल का नारा दे रही है और चार बागान श्रमिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रही है। पार्टी माइक्रो-लेवल बुथ मैनेजमेंट पर जोर दे रही है ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचा जा सके।

महाराष्ट्र विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास बनाने के आरोप में पांच गिरफ्तार, कर्मचारी भी शामिल

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र पुलिस ने विधानसभा सत्र के दौरान फर्जी प्रवेश पास बनाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया जब एक शिकायत में अनधिकृत पासों के वितरण का जिक्र किया गया। सत्र के दौरान राज्यमंत्री उदय सामंत ने यह मुद्दा उठाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और इस रकेट से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान केशव गुजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबाले (40) और स्वप्निल रमेश तावडे (40) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक और भी संदिग्ध इसमें शामिल हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस मामले ने एक अहम विधायी सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर गंभीर विचारों को जन्म दे दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि फर्जी पास कैसे बनाए गए, इस प्रक्रिया को किसने अधिकृत किया और क्या किसी अदरुनी व्यक्ति के समर्थन से यह जालसाजी संभव हुई।

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र पुलिस ने विधानसभा सत्र के दौरान फर्जी प्रवेश पास बनाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया जब एक शिकायत में अनधिकृत पासों के वितरण का जिक्र किया गया। सत्र के दौरान राज्यमंत्री उदय सामंत ने यह मुद्दा उठाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और इस रकेट से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान केशव गुजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबाले (40) और स्वप्निल रमेश तावडे (40) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक और भी संदिग्ध इसमें शामिल हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस मामले ने एक अहम विधायी सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर गंभीर विचारों को जन्म दे दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि फर्जी पास कैसे बनाए गए, इस प्रक्रिया को किसने अधिकृत किया और क्या किसी अदरुनी व्यक्ति के समर्थन से यह जालसाजी संभव हुई।

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र पुलिस ने विधानसभा सत्र के दौरान फर्जी प्रवेश पास बनाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया जब एक शिकायत में अनधिकृत पासों के वितरण का जिक्र किया गया। सत्र के दौरान राज्यमंत्री उदय सामंत ने यह मुद्दा उठाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और इस रकेट से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान केशव गुजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबाले (40) और स्वप्निल रमेश तावडे (40) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक और भी संदिग्ध इसमें शामिल हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस मामले ने एक अहम विधायी सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर गंभीर विचारों को जन्म दे दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि फर्जी पास कैसे बनाए गए, इस प्रक्रिया को किसने अधिकृत किया और क्या किसी अदरुनी व्यक्ति के समर्थन से यह जालसाजी संभव हुई।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा: स्वामिनेई के पोस्टर्स पर गरमाया माहौल, विधायकों के बीच धक्का-मुक्की

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ईरान के पूर्व सूप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीडीपी (पीडीपी) के विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधायक हाथों में खामेनेई के पोस्टर और तस्वीरें लेकर सदन में पहुंचे और उनके समर्थन में नारेबाजी की। इसी बीच कुछ विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हो गई, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई।



प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना था कि किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है और इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी पार्टी और जम्मू-कश्मीर सरकार ईरान के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ल खान भी इस तरह की घटनाओं की निंदा कर चुके हैं। गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले में खामेनेई की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में

जवाब में बीजेपी विधायक युद्धवीर सेठी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी की, जिससे विवाद और बढ़ गया। देखते ही देखते बहस ने उस रूप ले लिया और दोनों पक्षों के विधायकों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करने की कोशिश की। हालांकि, हंगामा बढ़ने के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।

छोटी बच्ची ने भेंट किया खिलौना बुलडोजर हंसी नहीं रोक सके सीएम योगी

-बच्ची के साथ खिंचवाई तस्वीर, खूब पढ़ने की दी नसीहत, गौरखपुर दौरे पर ही सीएम

गोरखपुर (एजेंसी)। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान उन्हें कानपुर से आई एक छोटी बच्ची ने खिलौना बुलडोजर भेंट किया। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी हंसने लगे। सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने पहले तो बच्ची को पास बुलाया, फोटो खिंचवाई और फिर उसे खूब पढ़ाई करने की नसीहत दी। बाद में सीएम ने बच्ची को उसका खिलौना वापस कर दिया। फिलहाल, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुद सीएम योगी के ऑफिस की ओर से इसको शेयर किया है। इसमें लिखा है। यह नसा सा उधार बड़े विश्वास का प्रतीक है, यह भरोसे की मासूम अर्पित है... आज सुबह गोरखनाथ



मंदिर में भ्रमण के दौरान सीएम को कानपुर की पांच साल की यशस्विनी ने बुलडोजर खिलौना भेंट किया। वीडियो को मिनटों में हजारों लोग ने देखा। बता दें इससे पहले सीएम योगी ने शुक्रवार को राम नवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान राम भारतीय चेतना का आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि राम करुणा और

कर्तव्य के बीच एक अद्भुत संतुलन का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि धर्म, सत्य और मर्यादा के सर्वोच्च प्रतीक भगवान राम की जयंती पर सभी भक्तों और प्रदेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें गुरुवार को गोरखपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और चेतनावनी दी कि गरीबों को परेशान करने वालों को बखूबा नहीं जाएगी। सीएम ने जनता दर्शन में 200 लोगों से मुलाकात की, उनके आवेदन लिए और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेगी। योगी ने संबोधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आवेदन भेजे, और उन्हें निर्देश दिया कि वे समय पर और संतोषजनक ढंग से उनका निपटारा करें।

अमेरिका में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले... भारत में क्या स्थिति

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (इंएमएस)। अमेरिका में फिर कोरोना के मामले में अचानक बढ़ोतरी ने चिंता पैदा कर दी है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरस का एक नया वेरिएंट 3.2 वेरिएंट सामने आया है। सीडीसी के अनुसार, 11 फरवरी तक बीए.3.2 वेरिएंट 23 देशों में मिला है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह वेरिएंट इम्यून सिस्टम को आंशिक रूप से चकमा देने की क्षमता रखता है, जिससे दोबारा इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि मौजूदा स्थिति पहले जैसी

गंभीर नहीं है। पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सिन ले चुके हैं या मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने चिंता पैदा कर दी है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरस का एक नया वेरिएंट 3.2 वेरिएंट सामने आया है। सीडीसी के अनुसार, 11 फरवरी तक बीए.3.2 वेरिएंट 23 देशों में मिला है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह वेरिएंट इम्यून सिस्टम को आंशिक रूप से चकमा देने की क्षमता रखता है, जिससे दोबारा इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि मौजूदा स्थिति पहले जैसी

समय-समय पर इसके केस बढ़ते-घटते रहने वाले हैं। हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ नए वेरिएंट के आने का मतलब यह नहीं है कि फिर से महामारी जैसी स्थिति बनेगी। जानकार डॉक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस अब एक एंडेमिक बीमारी बन चुका है, यानी यह पूरी तरह खत्म नहीं होगा बल्कि समय-समय पर नए रूप में आता रहेगा। डॉक्टर का कहना है कि नए वेरिएंट की वजह से इंफेक्शन के मामले बढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में लक्षण हल्के हैं

मध्यम रह सकते हैं, जैसे बुखार, खांसी और थकान। कुछ लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट का मानना है कि घबरापने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हेल्थ सिस्टम अब पहले से ज्यादा तैयार है और टेस्टिंग, इलाज और वैक्सिनेशन के बेहतर इंतजाम मौजूद हैं। इसके बावजूद, निगरानी बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।



मलयालम को ताकतवर बनाने का श्रेय लेने की होड़



उमेश चतुर्वेदी

भाषायी अस्मिता के लिहाज से देखें तो केरल का यह कदम बेहद क्रांतिकारी और भारतीय भाषाओं के हित में है। लेकिन कर्नाटक की आपत्तियों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल के कासरगोड जिले में मलयालम की बजाय कन्नड़ भाषी लोग ज्यादा है।

केरल में विधानसभा चुनावों के बीच मलयालम को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलने का श्रेय लेने का सियासी खेल बढ़ता जा रहा है। राज्य का नाम केरलम किया जाना और इसके हफ्तेभर बाद ही मलयालम को आधिकारिक भाषा की मंजूरी मिलना कुछ लोगों की नजर में भले ही संयोग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने की औपचारिकता भर बाकी है। इस संदर्भ में राजनीतिक दलों द्वारा इन दोनों कदमों का श्रेय लेने की होड़ मचना स्वाभाविक है। लेकिन भाषा विधेयक को लेकर केरल की सीमाओं के बाहर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि गैर हिंदीभाषी इलाके अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी अस्मिता से जोड़कर देखते हैं। हिंदीभाषी राज्यों में अपनी हिंदी या स्थानीय भाषाओं को लेकर ऐसी सोच नहीं दिखती।

मलयालम को केरलम की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग बहुत पुरानी है। इस दिशा में पहला प्रयास करीब दस साल पहले कांग्रेस की अगुआई वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ की सरकार ने किया था। 2015 में ओमन चांडी सरकार ने इस विधेयक को पारित कराया था। लेकिन तब इस विधेयक पर पड़ोसी कर्नाटक सरकार ने कड़ा एतराज जताया था। जब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति ने इसे 1963 के ऑफिशियल भाषा एक्ट के नियमों को हटाकर जमा करने के सुझाव के साथ वापस भेज दिया था। फिर दस साल बाद मौजूदा वाममोर्चा की सरकार ने इसे नए रूप में पारित किया। इस बार भी कर्नाटक इस कानून का विरोध कर रहा है।

अब तक केरल में अंग्रेजी के साथ ही मलयालम को आधिकारिक भाषा के तौर पर प्रतिष्ठा रही है। लेकिन नए कानून के तहत सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक मलयालम को पहली भाषा के तौर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाना जरूरी होगा। इसके साथ ही अदालती फैसलों और कार्यवाही भी अनिवार्य तौर पर मलयालम भाषा में अनुदित की जाएगी। अब से राज्य विधानसभा में सभी बिल और अध्यादेश मलयालम में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही, अंग्रेजी में प्रकाशित महत्वपूर्ण केंद्रीय और राज्य कानूनों का भी मलयालम में अनुवाद होगा। नए कानून के तहत सूचना तकनीकी विभाग को मलयालम के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रूमेंट विकसित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। राज्य सचिवालय में मौजूदा पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म (ऑफिशियल



केरल विधानसभा चुनाव 2026

लैंग्वेज) विभाग का नाम बदलकर मलयालम भाषा विकास विभाग किया जा रहा है। इन कदमों के साथ ही राज्य में मलयालम भाषा विकास निदेशालय भी गठित किया जाएगा। भाषायी अस्मिता के लिहाज से देखें तो केरल का यह कदम बेहद क्रांतिकारी और भारतीय भाषाओं के हित में है। लेकिन कर्नाटक की आपत्तियों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल के कासरगोड जिले में मलयालम की बजाय कन्नड़ भाषी लोग ज्यादा है। राज्य में इसी तरह तमिल, तुलु, गुजराती और कोंकणीभाषी लोग भी हैं। उनकी अपनी भाषाओं में पढ़ाई वाले स्कूल भी हैं। हालांकि मलयालम भाषा कानून का विरोध तमिल मूल के लोगों ने तो नहीं किया है, लेकिन कर्नाटक के तर्कों में उनकी भी बातें एक तरह शामिल हैं। कर्नाटक सरकार का तर्क है कि यह कानून केरल में रहने वाले कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यकों की भाषाई अस्मिता के लिए खतरा है। यह कानून, कर्नाटक भाषियों के अधिकारों का उल्लंघन है। कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का तर्क है कि कासरगोड और केरल के दूसरे कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्र अभी स्कूलों में कन्नड़ को पहली भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। केरल में स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाई जाती रही है। इसलिए माना जाता है कि केरल में हिंदीविरोधी

माहौल नहीं है। लेकिन दिलचस्प यह है कि केरल के विद्वान भी इस कानून के पक्ष में तर्क देते वक्त केन्द्र सरकार पर केरल में हिंदी धोपने का आरोप लगाने से नहीं हिचक रहे। दिलचस्प यह है कि ऐसा ही आरोप कर्नाटक की ओर से लगाया जा रहा है, बस वहां हिंदी की जगह मलयालम को धोप जाने की बात हो रही है। केरल सरकार ने हालांकि सफाई दी है कि जिनकी मातृभाषा तमिल, कन्नड़, तुलु या कोंकणी है, उनके लिए भी कानून में प्रावधान हैं। इस कानून में इस बात की चर्चा है कि राज्य के भाषायी अल्पसंख्यक अपनी भाषा में राज्य सचिवालय, विभागों और स्थानीय सरकारी कार्यालयों से पत्राचार कर सकेंगे। इसके साथ ही, मलयालम के अलावा दूसरी मातृभाषा वाले छात्रों को नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल भाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे। इसी तरह दूसरे राज्यों या विदेश से आने वाले छात्रों को नौवीं, दसवीं और हायर सेकेंडरी स्तर पर मलयालम की परीक्षा देने से छूट मिलेगी। मलयालम को आधिकारिक भाषा बनाने का स्थानीय नागरिक स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस कानून के नाम से ही अलगाववादी और वर्चस्ववादी झलक मिलती है। केरल के बौद्धिकों का एक वर्ग का कहना है कि बेहतर होता है कि इस कानून का नाम 'मलयालम भाषा

एक्ट 2025' की जगह 'केरल स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2025' होता। इससे समावेशी संदेश जाता। यहां के बौद्धिकों का तर्क है कि इस विधेयक में मलयालम की जगह बेहतर होता कि राज्य में प्रयोग में लाई जाने वाली तमिल, कन्नड़, कोंकणी, तुलु और गुजराती का भी जिक्र होता। केरल में जंगलों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की अपनी भाषाएं भी हैं। वे मलयालम का इस्तेमाल कम करते हैं। इसलिए एक वर्ग का मानना है कि उनकी भाषाओं की अस्मिता की रक्षा का बोध भी इस कानून में होना चाहिए था।

बेशक केरल के विधानसभा चुनाव में मलयालम को आधिकारिक दर्जा मिलना बड़ा मुद्दा होगा। राज्य की राजनीति में प्रभावी दखल देने की ताकत में बैठी भाजपा, कांग्रेस और वाममोर्चा, सभी इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां के बौद्धिक समाज की चिंता है कि इस विधेयक से राज्य में एक भाषा के वर्चस्व का भाव पैदा हो सकता है। ऐसा लगता है कि जिन लोगों की भाषा मलयालम नहीं है, उनकी प्रशंसा और शासन से जुड़ी चिंतों को अंग्रेजी के जरिए हल किया जा सकता है। लेकिन केरल के बौद्धिक मानते हैं कि राज्य के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा से इतर वाले लोगों की समस्याओं का समाधान अंग्रेजी के जरिए नहीं हो सकता। इसलिए भाषा विकास विभाग और निदेशालय को सिर्फ मलयालम भाषा तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि केरल की सभी भाषाओं के लिए होना होगा। केरल में यांग उठ रही है कि वहां के सिविल सर्विस सुधार विभाग को मलयालम भाषा विकास विभाग के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। कानून में इस विभाग के पुनर्गठन और मलयालम भाषा व कास निदेशालय बनाने का प्रावधान है। यहां के भाषाशास्त्री इसे स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। लेकिन, इसमें मलयालम के साथ दूसरी भाषा समूहों का भी प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि भाषा का नाम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। शायद यही वजह है कि मलयालम भाषा कानून के स्वागत के साथ ही दूसरी भाषाओं को तवज्जो देने की मांग हो रही है।

मातृभाषा से इतर समूहों से आने वाले लोग किसी भी भाषा को अवसरों और जरूरत के लिहाज से सीखते हैं। सीखने की इस प्रक्रिया में मजबूरी की बजाय उत्साह जुड़ जाता है तो भाषाएं समृद्ध होती हैं और वे सौहार्द का प्रतीक बनती हैं। आधिकारिक भाषा बनने के बाद मलयालम भी उसी तरह उम्मीद की भाषा बन, शायद यही केरल के बौद्धिक चाहते हैं। मलयालमभाषियों की इस सोच को हिंदीभाषी विद्वानों, राजनेताओं और प्रशासकों को प्रेरित होना चाहिए।

संपादकीय

मेडिकल छात्रा का मानसिक शोषण

विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे भविष्य की आस रखने वाले छात्रों का कई बार उनके संस्थानों में शोषण किया जाता है जिससे प्रसिद्ध होकर अक्सर छात्र छात्राएं ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके परिवारों को जिंदगी भर एक गहरा जख्म दे जाते हैं। उत्तराखंड देहरादून के एक नामी मेडिकल कॉलेज की छात्रा का प्रकरण भी ऐसे ही मानसिक शोषण से जुड़ा हुआ है जिसमें मेडिकल की एक प्रतिभावान छात्रा को इस संस्थान की विभाग अध्यक्ष द्वारा प्रताड़ित करने का मामला देखने को मिला है। विभाग अध्यक्ष महिला चिकित्सक द्वारा पदभार संभालने के बाद मेडिकल की छात्रा को लगातार प्रताड़ित करना शुरू किया गया और आखिरकार होनहार छात्रा इस प्रताना को झेल नहीं पाई और उसने अपनी ही कार में अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह घटना एक शिक्षित समाज में बेहद शर्मनाक है खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में जहां राष्ट्र के उत्थान के लिए होनहार भविष्य तैयार किए जाते हो, वहां ऐसे प्रतिभावान छात्रों के भविष्य को कुचलने का काम कुछ मानसिक विकृति के लोग भी करते हैं। शिक्षक की भूमिका अपने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए संवारने की होती है लेकिन अक्सर कुछ शिक्षक विशेष छात्रों के खिलाफ ऐसी मनोवृत्ति बना लेते हैं जिससे छात्र अवसाद में चले जाते हैं। एक शिक्षक के लिए सभी छात्रों का दर्जा बराबर होना चाहिए लेकिन जब शिक्षक पक्षपात पर उतारू हो जाए और दूसरे शिक्षक के कुछ खास छात्रों से लगाव रखने के कारण ऐसे छात्रों से रंजित रखने लगे तो फिर छात्रों को अपनी राह तलाश में ही मुश्किल हो जाती है। प्रकरण में पुलिस ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है लेकिन यहां संस्थान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जिसने इस प्रकरण में कार्रवाई करने के बजाय मेडिकल छात्रा को ही मानसिक अवसाद का शिकार बताया है और कहा है कि उक्त छात्रा पहले भी दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक संस्थान में कोई छात्र या छात्रा मानसिक रूप से परेशान है तो संस्थान को अपनी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ना की किसी खास शिक्षक का पक्ष लेना चाहिए। उक्त छात्रा के मामले में एक होनहार युवा राष्ट्र की सेवा में आने से पहले ही अपना जीवन छोड़ चुका है जिसके लिए संस्थाओं को भी निश्चित तौर पर जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यदि इसी प्रकार के हालात शैक्षिक संस्थानों में प्रकाश में आते रहेंगे तो फिर अभिभावकों के लिए भी अपने बच्चों को घर से दूर भेजना किसी प्रताड़ना से कम नहीं होगा। देहरादून पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वह इस प्रकरण में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करें तथा छात्रा द्वारा की गई वॉयस रिकॉर्डिंग एवं उसके साथ पूर्व में किए गए प्रताड़ित व्यवहार की जांच गंभीरता से करें। यू ही एक होनहार छात्रा के साथ हुए जुल्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जो लोग भी इस कृत्य के पीछे पूर्वाग्रह से प्रसिद्ध होकर लगे हुए थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे लोग होनहारों का जीवन बर्बाद ना कर पाएं।



मनोज कुमार अग्रवाल

यह कैसी बिडम्बना है कि इक्कीसवीं सदी में पहुंच कर भी भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी टोना टोटका डायन भूत प्रेत और बाबाओं के चमत्कार पर भरोसा रखता है इतना ही नहीं ये संत के चोले में छिपे शैतान न सिर्फ अरबों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं वरन हर तरह की पोपलीला भी टकर रहे हैं धर्म की आड़ में आर्थिक दैहिक शोषण बलात्कार, हत्या, ब्लैकमेलिंग करने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले दोंगी बाबाओं की सूची में अब एक नया नाम नासिक के अशोक खरात का जुड़ गया है। अशोक खरात की कहानी भी राम रहोम और आसाराम जैसे लोगों से अलग नहीं है। धर्म के नाम पर अपनी निजी जीवन की परेशानियों के निराकरण के लिए बाबा पर भरोसा कर आए लोगों को वाकजाल में फंसाना, उनसे धन ऐंठना और महिलाओं का यौन शोषण करना धंधा बन गया है। अब सामने आया है कि लम्बे समय से ये अपराध होते रहे और दोंगी व्यक्ति खुद को भगवान बलात्कार दिखाता रहते तो यह न स्वस्थ समाज की पहचान है, न स्वस्थ राजनीति और प्रशासन की। क्योंकि ताकतवर लोगों के प्रोत्साहन के बिना ठगी और अपराध की ऐसी दुकानें

समाज के लिए खतरा हैं धर्म के चोले में पनपते कालनेमी

चल ही नहीं सकती। हो सकता है कि अभी पुलिस हिरासत में आए इस अपराधी को कुछ वक्त तक सलाखों के पीछे ही रहना पड़े, लेकिन इस समय ज्यादा चिंता की बात यह है कि समाज जिस तरह चमत्कारों, अंधविश्वासों और अताकिक प्रथाओं की सलाखों में कैद है, उससे वह कब आजाद हो पाएगा। कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस महाराष्ट्र में संत तुकाराम संत नामदेव महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जैसे महापुरुषों की कतार दी, वहां अशोक खरात लोगों को अंधविश्वास की आग फैलाने का मौका मिला। नरेंद्र दामोदरकर जैसे लोग अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज उठाए तो उनकी हत्या कर दी जाए और अशोक खरात जैसे लोग अंधश्रद्धा के बूते खुद को गांडमैन कहलवाए। यह बेहद हैरत की बात है क्योंकि सरकारों भी ऐसी बातों पर तभी एक्शन लेती है जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है। यूं तो देश का राजनीतिक दल इस किस्म के बाबाओं से खुद को दूर रखा है, हर दल में ऐसे नेता मिल जाएंगे, जो दोंगी चोगों को बढ़ावा देते रहें हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में समस्या कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है, यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज जब राष्ट्रपति के गरिमायुगी पद पर आसीन माननीय किसी संत के स्थान पर आकर कथित एकांतिक वातालाप के लिए समय दे रही हैं ऐसे समय में समाज संत और कालनेमी संत की पहचान कैसे करे? विचारणीय बात यह है कि भगवदभक्ति में लगे लोगों को भीतिक चकाचौंध की दरकार क्यों होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल की परतें खोलें तो समझ आता है कि ऐसे लोगों को न भगवदभक्ति से मतलब है, न धर्म की रक्षा से, इन्हें तो अपने उन राजनैतिक और व्यापारी आकाओं की सेवा करनी है, जिनके काले धन को धर्म के धंधे से ये सफेद करते हैं। अशोक खरात का मामला भी कुछ

ऐसा ही लगता है। ताजा जानकारी के अनुसार नासिक में कथित हफ्ताजी बाबाह्व अशोक खरात के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नरबलि और अंधश्रद्धा से जुड़े गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। नासिक पुलिस ने खरात के खिलाफ अब तक कुल 8 एफआईआर दर्ज की हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस ने आरोपी को लाइसेंस रिवॉल्वर भी जब्त कर ली है और उसका लाइसेंस रद्द करके भीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, ताजा एफआईआर उस व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसके खिलाफ पहले अशोक खरात ने खुद मामला दर्ज कराया था। अब उसी व्यक्ति ने खरात पर संगीन आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दावा किया गया है कि 2018 से 2025 के बीच आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर शिकायतकर्ता से भारी आर्थिक ठगी की आरोप है कि फरवरी 2020 से मार्च 2026 के बीच आरोपी ने एक महिला को अपने ऑफिस बुलाया। तांबे की बोटल में 'मंत्रित पानी' पिलाया गया। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो बाद में गर्भपात के लिए दवाव डाला गया। मना करने पर जान और बच्चे को खरते की धमकी दी गई। इस श्राथमिक रिपोर्ट में आरोप है कि 'पितृव्य औषधि' के नाम पर महिला का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। स्वयंभू चमत्कारी बाबा यह शस्त्र अब महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाने के आरोपों में घिरा हुआ है। दरअसल 29 दिसंबर 2025 को अशोक खरात खुद वावी पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग उसके अपत्तिजनक फोटो और

वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। शुरूआत में मामला ब्लैकमेलिंग का लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मोबाइल डेटा और साइबर जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, उन्हें भी अदालत से राहत मिल गई। वहीं से पुलिस को शक हुआ कि मामला कुछ और ही है। करीब डेढ़ महीने बाद 18 फरवरी 2026 को शिर्डी से एक और शिकायत सामने आई। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे एआई से तैयार अशोक फोटो भेजकर धमकाया गया। इसी दौरान एक अहम गवाह सामने आया, जिसने पुलिस को कुछ ऐसे वीडियो दिखाए जिनमें कई महिलाओं के साथ अशोक खरात की आपत्तिजनक हरकतें नजर आईं। आरोप है कि वह महिलाओं को धार्मिक झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उनका शोषण करता था। गवाह पहले डरा हुआ था, लेकिन पुलिस की थुराशा मिलने के बाद उसने ये सबूत सौंप दिए। मामला आगे बढ़ा तो 10 मार्च 2026 को अशोक खरात के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और एयरपोर्ट पर उसे रोक दिया गया। फिर फुडनवीस सरकार ने 13 मार्च को एसआईटी गठित की और लगातार नए खुलासे सामने आने लगे। 17 मार्च को सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक महिला ने बताया कि अशोक खरात ने खुद को दैवी शक्तियों वाला बलात्कार उसे अनुष्ठान के नाम पर अपने ऑफिस बुलाया। वहां उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से कई अहम सबूत मिले। आरोपी के पास से लाखों रुपये नकद, लैपटॉप, डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस और हथियार तक बरामद किए गए हैं।

जलवायु परिवर्तन: भविष्य नहीं, वर्तमान का महाविनाशकारी संकट

अस्तुलन सीधे-सीधे मानव जीवन, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस बदलते मौसम ने सबसे ज्यादा मनुष्य के स्वास्थ्य पर हमला किया है। भारत के संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अनेक शहरों में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पहले 45 डिग्री को ही अत्यधिक गर्मी माना जाता था। अब असामान्य गर्मी ने फरवरी और मार्च जैसे महीनों को भी झुलसाना शुरू कर दिया है। हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। इसका असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि बिजली, पानी, खेती, श्रम, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बढती गर्मी ने केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि वन्यजीव, पेड़-पौधे और सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी संकट में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण मानव का विकास मॉडल है। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगिकरण और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पृथ्वी को लगातार गर्म कर रहा है। आज वैश्विक तापमान लगभग एक लाख 25 हजार वर्षों के उच्चतम स्तर के आसपास पहुंच चुका है। यह स्थिति बताती है कि समस्या प्रकृति में नहीं, बल्कि मानव की जीवनशैली और विकास की दिशा में है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां इस संकट को और अधिक खतरनाक बना रही हैं। दुनिया के अनेक हिस्सों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। युद्ध केवल मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को ही नष्ट नहीं करते, बल्कि पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक, रसायन, धातु, ईंधन और आग से वातावरण में भारी मात्रा में जहरीली गैस फैलती है। तेल भंडारों में आग, रासायनिक संयंत्रों का

नष्ट होना और सैन्य गतिविधियां वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस प्रकार युद्ध और जलवायु परिवर्तन मिलकर पृथ्वी को दोहरे संकट की ओर धकेल रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसे नदियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है। दूसरी ओर समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि समुद्र स्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में तटीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। यह केवल पर्यावरण संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी बन सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती नहीं की गई, तो तापमान के नए-नए रिकॉर्ड टूटते रहेंगे और पृथ्वी रहने योग्य स्थान कम होती जाएगी। जल संकट, खाद्य संकट, स्वास्थ्य संकट और प्रवासन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। दुनिया के अनेक वैज्ञानिक अब चेतवनी दे रहे हैं कि यदि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया, तो पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ सकता है। लेकिन इस संकट में ही अवसर भी छिपा हुआ है। यह समय विकास मॉडल को बदलने का है। उर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। शहरों को कंक्रिट के जंगल बनाने के बजाय हरित शहर बनाना होगा। जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाना होगा। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चरण और नदियों के संरक्षण पर गंभीरता से काम करना होगा। कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना होगा, कम पानी वाली फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जिला

स्तर पर हीट एक्शन प्लान, जल संरक्षण योजना, वृक्षारोपण अभियान और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम लागू करने होंगे। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल सरकार नहीं जीत सकती, इसके लिए समाज, उद्योग, वैज्ञानिक और आम नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा। दुनिया की महाशक्तियों के लिए यह समय सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। यदि वे केवल आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति की दौड़ में ही उलझी रहें और पृथ्वी के भविष्य की चिंता नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्हें यह समझना होगा कि पृथ्वी बचेगी तो अर्थव्यवस्था भी बचेगी, मानव सभ्यता भी बचेगी और विकास भी बचेगा। यदि पृथ्वी ही तपती जाए और असंतुलित हो गई, तो सारी प्रगति बेकार हो जाएगी। आज आवश्यकता है कि दुनिया की महाशक्तियां कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कटौत और बाध्यकारी नीतियां बनाएं, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करें, वनों की कटाई रोकें और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि अनेक क्षेत्र रहने योग्य नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चुनौती नहीं, वर्तमान का संकट है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को एक असंतुलित और तपती हुई पृथ्वी विरासत में मिलेगी। यह तपती हुई पृथ्वी मानव जीवन के लिए विनाश का कारण भी बन सकती है। लेकिन यदि दुनिया समय रहते चेत गई, तो ही संकट एक नए, संतुलित और टिकाऊ विकास मॉडल की शुरुआत भी बन सकता है। पृथ्वी को बचाना अब विकल्प नहीं, मानव अस्तित्व की अनिवार्यता बन चुका है। (खक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

